



संख्या—cm-215  
06/07/2019

### मुख्यमंत्री ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ की पूर्व तैयारियों की समीक्षा

पटना, 06 जुलाई 2019 :- मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ की पूर्व तैयारियों की समीक्षात्मक बैठक हुयी। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव श्री प्रत्यय अमृत ने अपने विभाग द्वारा इस संबंध में की जा रही तैयारियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्रधान सचिव ने बताया कि इसरो के साथ जल्द ही बिहार सरकार के साथ एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर हो जायेगा, जिससे राज्य के बहुआयामी आपदा जोखिम आकलन में सहायता मिलेगी।

मौसम विज्ञान केंद्र के प्रतिनिधि ने 5 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में सामान्य से ज्यादा वर्षापात की संभावना जताई है। कृषि विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, जल संसाधन विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ऊर्जा विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग, सहकारिता विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग एवं संबंधित अन्य विभागों के प्रधान सचिव/सचिवों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े सभी जिलाधिकारियों ने बाढ़ एवं सुखाड़ की परिस्थिति में की जा रही तैयारियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

कृषि विभाग के प्रधान सचिव श्री सुधीर कुमार ने कृषि इनपुट सब्सिडी के लिए अब तक निर्गत राशि एवं लाभार्थियों की संख्या की जानकारी दी। वर्षापात कम या अधिक होने की स्थिति में वैकल्पिक फसल के लिए बीज की उपलब्धता के संबंध में भी जानकारी दी गई।

सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अतुल प्रसाद ने फसल सहायता योजना के संबंध में जानकारी दी। वहीं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव श्री जितेंद्र श्रीवास्तव ने वर्तमान में भू-जल स्तर की स्थिति की जानकारी दी। गुणवत्तापूर्ण पानी की उपलब्धता कराने के संबंध में, जीर्ण-शीर्ण चापाकलों को हटाना, सार्वजनिक कुओं के जीर्णोद्धार के लिये बनायी जा रही कार्ययोजना के संबंध में भी जानकारी दी। पेयजल में होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री चैतन्य प्रसाद ने मुख्यमंत्री को नगर निकायों में जलापूर्ति संबंधी अद्यतन स्थिति की जानकारी दी।

पशु एवं मत्स्य विभाग ने पशु रोग नियंत्रण की व्यवस्था, टीकाकरण की व्यवस्था, पेयजल, पशुचारा की व्यवस्था, पशुओं में होने वाले रोगों की दवा की उपलब्धता, जिला स्तर पर आपदा कोषांग का गठन, कैटल ट्रैप का निर्माण इत्यादी की जानकारी दी। जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार सिंह ने नहरों में जल उपलब्धता की स्थिति एवं तटबंधों की सुरक्षा स्थिति, बाढ़ पूर्व निरोधक कार्य, बाढ़ सुरक्षात्मक उपाय इत्यादि की जानकारी दी।

बैठक में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहा कि मौसम विज्ञान के प्रतिनिधि के मुताबिक इस बार भी कम वर्षापात की आशंका है, अतः संभावित सूखे की स्थिति के लिये आपलोगों ने अपने विभागों के बारे में तैयारियों की जानकारी दी है, साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों ने बाढ़ की स्थिति एवं सुखाड़ की स्थिति में

अपने-अपने जिलों में इसके लिये की जा रही तैयारियों के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में विभिन्न बिन्दुओं पर फीडबैक भी मिला है। 13 तारीख को बिहार विधानमण्डल के सेंट्रल हॉल में विधायकों, विधान पार्षदों के साथ भी इस संबंध में बैठक होगी और उनसे अपने-अपने क्षेत्र के संबंध में सुझाव एवं फीडबैक लिये जायेंगे। जलवायु परिवर्तन होने से वर्षापात कम हो रहा है। पिछले 13 वर्षों में बिहार में वर्षापात 1000 मी०मी० से कम ही हुआ है लेकिन पिछले वर्ष सूखे की स्थिति रही और इस वर्ष भी इसकी संभावना बतायी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित विभाग आपस में को-ऑर्डिनेशन करते रहें और फीडबैक के आधार पर संभावित परिस्थितियों से निपटने के लिये तैयार रहें। उन्होंने कहा कि कृषि इनपुट अनुदान और फसल सहायता योजना का लाभ सभी किसानों को दिलाना सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सूखे की स्थिति में वैकल्पिक फसल के लिये भी योजना बना लेनी होगी। पशु शिविरों को कारगर करना होगा। कैटल ट्रैप के साथ-साथ तालाबों को भी इम्प्रूव करना होगा। तालाबों की उड़ाही कराकर वहाँ सोलर पंपिंग सेट लगाने की व्यवस्था हो जाने से पानी की व्यवस्था सुनिश्चित हो जायेगी और पशुओं को इससे काफी राहत मिलेगी। पशुओं के बीमारियों के इलाज के लिये उपाय, पशुओं के नियमित टीकाकरण आदि की व्यवस्था रखें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर भी अमल करना होगा। चेक डैम के लिये भी काम करना होगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा के माध्यम से सार्वजनिक तालाबों, पोखर, आहर आदि की खुदाई में कितने काम किये जा रहे हैं, इसके बारे में विभाग एवं जिलाधिकारी आंकलन करवा लें। पेयजल की व्यवस्था, कृषि के लिये पानी की उपलब्धता, लोगों की बीमारियों के बचाव के लिये संबंधित विभागों को तैयार रहना होगा। नए तकनीक वाले और ज्यादा गहराई वाले चापाकल लगाए जाएं। मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि जलाशयों का अपने स्तर से दौरा कर वहाँ की स्थिति का आकलन कर लीजिए। उन्होंने कहा कि सूखे की स्थिति में जब कृषि क्षेत्र में लोगों को काम नहीं मिल पायेगा तो उनके वैकल्पिक रोजगार के लिये हमलोगों को काम करना होगा, इसके लिये कई प्रोजेक्ट बनाये गये हैं। मनरेगा, सड़कों का निर्माण, भवनों का निर्माण, स्कूल भवनों का निर्माण, हर घर नल जल योजना, पक्की गली नाली योजना, चापाकल की व्यवस्था करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वृक्ष लगाना, वृक्षों का रखरखाव करना जैसे कई कामों के माध्यम से लोगों को रोजगार दिलाया जा सकता है। इस बात का भी सर्वे करा लेना होगा कि जो लोग कृषि क्षेत्र में मजदूरी नहीं कर रहे हैं, उनके वैकल्पिक रोजगार क्या है। सभी विभाग इस बात के लिये प्रयास करें कि अधिक से अधिक लोगों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध करा सकें। हमलोगों ने बिहार का हरित आवरण क्षेत्र 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है और 17 प्रतिशत तक पहुँचने के लिये काम कर रहे हैं। जैसा कि वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने बताया है कि 1 अगस्त से डेढ़ करोड़ पेड़ लगाने के लक्ष्य पर काम किया जायेगा। पर्यावरण के कारण जलस्तर नीचे गिरता जा रहा है। लोगों को इस बात के लिये जागरूक करना होगा कि पीने के स्वच्छ पेयजल का दुरुपयोग न हो, इसके लिये भी प्रेरित करना होगा।

बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, ऊर्जा मंत्री श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, कृषि मंत्री श्री प्रेम कुमार, पथ निर्माण मंत्री श्री नंदकिशोर यादव, भवन निर्माण मंत्री श्री अशोक चौधरी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री विनोद नारायण झा, स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पाण्डेय, लघु जल संसाधन मंत्री श्री नरेंद्र नारायण यादव, जल संसाधन मंत्री श्री संजय झा, आपदा प्रबंधन मंत्री श्री लक्ष्मेश्वर राय सहित मुख्यमंत्री के परामर्शी श्री अंजनी कुमार सिंह, मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार, पुलिस महानिदेशक श्री गुप्तेश्वर पाण्डेय, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री ब्यासजी, संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के अपर सचिव श्री चन्द्रशेखर

सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यगण, समादेष्टा एन0डी0आर0एफ0, समादेष्टा एस0डी0आर0एफ0 सहित संबद्ध विभागों के अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

\*\*\*\*\*